भारत में नगद रहित अर्थव्यवस्थाः नोटबंदी की भूमिका

ज्योति लोखंडे,
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
डॉ. पूर्णिमा जोशी
प्राध्यापक, वाणिज्य संकाय, सत्य सांई महिला महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)
डॉ. राखी सक्सेना
प्राध्यापक, वाणिज्य संकाय, कैरीयर कॉलेज भोपाल (म.प्र.)

सारांश :–

वर्तमान समय में विश्व के सभी देश नगदी से नगद रहित अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। नगद रहित अर्थव्यवस्था वह होती है, जिसमें धन का अंतरण (ट्रांजैक्शन) नगद रूपयों के स्थान पर क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से किये जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत हद तक कृषि प्रधान और ग्रामीण है, जिसमें अधिकतम धन का अंतरण नगद लेनदेन के द्वारा ही किया जाता है। भारत में अभी भी अनेक लोगों के पास बैंक खाते, स्मॉर्ट फोन, इंटरनेट या ऑनलाइन भुगतान की विधियों को समझने और उनका उपयोग करने हेतु आवश्यक बुनियादी संशाधनों की कमी है। इसलिए, ग्रामीण भारत तथा छोटे शहरों में डिजिटल लेन–देन को सरल व सुलभ बनाने हेतु डिजिटल सेवाओं के व्यापक कार्यान्वयन की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता दर, बहुभाषा का उपयोग, अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ, नकदी रहित लेन–देन को अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इसी कारण से भारत के छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नगद के द्वारा ही लेनदेन, व्यापार आदि अधिक मात्रा में किया जाता है। हॉलांकि 2016 में भारत सरकार द्वारा नोटबंदी और कोविड की वैश्विक महामारी के कारण विगत वर्षों में सिर्फ महानगरीय या बड़े नगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में नगद रहित लेनदेन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और अब हम कई विकसित देशों से भी अधिक नगद रहित लेनदेन कर रहे हैं, और तेजी से नगद रहित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं।

जिससे अब नगद के रखरखाव में कमी के साथ ही काले धन, नकली नोटों की समस्या आदि में भी कमी आई है और अधिकतम अंतरण (ट्रांजैक्शन) पारदर्शी रूप से हो रहे हैं।

परिचय :–

नगद रहित अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकॉनमी) एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में नगद का उपयोग नहीं होता है और सभी तरह के ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जैसे कि डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, पेमेंट सिस्टम जैसे इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), यूपीआई, विभिन्न ऐप्स आदि के जरिए किए जाते हैं। आज, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस सिर्फ महानगरीय भारत में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो पेपर करेंसी नोट रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। एक कहावत के अनुसार पैसा बेकार है, नगद फ्लो बेकार है लेकिन नगद (कैश) राजा है। नगद को लेन–देन का वह कोई भी कानूनी तरीका माना जा सकता है जिस पर तुरंत मोलभाव किया जा सके और जिस पर कोई रोक न हो।

वर्तमान समय में हम दुनिया में नगद धन का इस्तेमाल करने वाले चौथे सबसे बड़े देश हैं। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में नगद का हिस्सा अभी भी सबसे अधिक है, जो कि भारत में सन 2021 में 14.40 प्रतिशत था अब वह 2026 में घटकर लगभग 11.00 प्रतिशत रह गया है। भारत में निजी अंतरण में नगद का हिस्सा 20 प्रतिशत है, और कार्ड ट्रांजैक्शन पर्सनल कंजम्पशन खर्च का 04 प्रतिशत है क्योंकि ज्यादातर लोग अनपढ़, गरीब हैं, छोटे–मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं और उनकी बैंकिंग की आदतें कम हैं। उनके लिए नगद लेन–देन का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है, जिसमें कोई झंझट नहीं होता है। नगद अंतरण तुरंत होता है और इसमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं होता। नगद धन लोगों और परिवारों को व्यावहारिक सामर्थ्य देता है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के क्रैश होन या सर्वर डाऊन होने, बिजली जाने और बीच में ट्रांजैक्शन खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। नगद के इस्तेमाल में डेबिट/क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है।

फ्रांस और नीदरलैंड जैसे सबसे ज्यादा नगद रहित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी, सभी उपभोक्ता अंतरण में नगद का हिस्सा अभी भी 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा होता है। आमतौर पर नगद रहित अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार कम होता है और काले धन में भी कमी आती है। वर्तमान में लगभग सभी देश नगद रहित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और कई देशों ने इस क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की भी की है, जिसमें हमारे देश भारत का नाम प्रमुख है। यह एक वैश्विक ट्रेंड है, जिसे हम भी तेजी से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।

- **भारत में पेपर करेंसी के जन्म का इतिहास :–**

18वीं सदी तक, भारत में आमतौर पर चांदी और सोने के सिक्के इस्तेमाल होते थे। 19वीं सदी में, ब्रिटिश लोगों ने कागजी मुद्रा (पेपर मनी) की शुरूआत करी थी। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने सरकार को पूरे ब्रिटिश इंडिया में नोट जारी करने का एकाधिकार दे दिया। ब्रिटिश इंडिया के नोटों का पहला सेट 'विक्टोरिया पोर्ट्रेट' सीरीज था, जो 10, 20, 50, 100, 1000 के रूप में जारी किया गया था। तत्कानीन भारत की दूसरी स्थानीय (कॉलोनियल) सरकारों ने भी इंडिया में अपने अधीन क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए नोट छापे। उदाहरण के लिए, फ्रांस के बैंक डेल इंडोचीन ने अपने "रूपी" नोट जारी किए और पुर्तगालियों ने "रुपिया" नोट जारी किए। 1928 में नासिक में भारत का पहला करेंसी प्रिंटिंग प्रेस बनने तक, ब्रिटिश लोगों के नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने छापे थे। 1935 में, भारत के धन का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी नई बनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को सौंप दी गई। आजादी के बाद पहला नोट 1949 में आया था। अगले कुछ सालों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग–अलग कीमत के नोट जारी किए गए, जिन पर स्मारकों की तस्वीरें और नोटों की नई "महात्मा गांधी सीरीज" के थे। 2016 में पहली बार 2,000 रूपये का करेंसी नोट जारी किया गया।

- **नगद रहित अर्थव्यवस्था में नोटबंदी का योगदान :–**

भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को मौजूदा 500 और 1,000 रूपये के करेंसी नोट बंद करने और 2000 के नए नोट लाने की घोषणा की, जिसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गई है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि सीमित नोटबंदी से

व्यापारी वर्ग के साथ–साथ कमाने वाले वर्ग को भी मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा नोटबंदी से बाद वाले को नुकसान होगा क्योंकि अगर रुपये में भारी गिरावट आई तो वे ज्यादा महंगाई की मार झेलेंगे। असल में, उन्होंने कहा कि रुपये की कीमत के बारे में सोचते समय इन दोनों समूहों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक नोटबंदी से होने वाली महंगाई की वजह से कमाने वाले वर्ग की असली मजदूरी कम हो जाएगी। भारत ने पहले भी सीमित नोटबंदी की हैः पहली बार 12 जनवरी 1946 (शनिवार), दूसरी बार 16 जनवरी 1978 (सोमवार), तीसरी बार 8 नवंबर 2016 (मंगलवार) को।

कई देशों ने इस नोटबंदी शब्द और पॉलिसी का इस्तेमाल बहुत अधिक रोक और परेशानी के साथ किया है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और आबादी पर बड़े पैमाने पर असर पड़ता है। 1850–1855 के बीच फ्रांस ने सबसे पहले नोटबंदी शब्द का इस्तेमाल किया था। घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नॉर्थ कोरिया, सोवियत यूनियन और भारत वे देश हैं जिन्होंने नोटबंदी की कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर नकली नोटों को रोकने के लिए पॉलीमर नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है जबकि भारतीय जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा अभी भी नोटबंदी के फायदे और नुकसान पर बहस कर रहा है। वेनेजुएला के बाद, अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार सबसे अधिक मूल्य वाली करेंसी को सर्कुलेशन से हटाने की योजना बना रही है।

मूडीज की 2010 के एक अध्ययन से पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट में 0.2 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है। मैकिन्से ग्लोबल इनसाइट्स रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 99 प्रतिशत से अधिक अंतरण अभी भी नगद रूप में होते हैं। बहुत कम नगद रहित लेनदेन के साथ क्या भारत के लिए बहुत अधिक मौके हैं? इसी पृष्ठभूमि में, यह शोध पत्र पेपर हमारी अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर, नकली करेंसी और नगद रहित अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- **नोटबंदी के फायदे :–**

कहा गया है कि नोटों की चमक और सिक्कों की खनक में नोटबंदी के बाद भी किसी के भी चेहरे पर खुशी लाने की ताकत है। नोटबंदी का अलग–अलग सेक्टर और पूरी

इकॉनमी पर बड़ा असर पड़ा है। नोटबंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ अच्छे प्रभाव इस प्रकार हुये हैं–

- भारत में करेंसी बनाए रखने का खर्च बहुत अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक हर साल करेंसी नोट और सिक्के छापने और सर्कुलेट करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लगभग 21,000 करोड़ रूपये खर्च करते हैं। नगद रहित अर्थव्यवस्था इस खर्च को कम करेगी।
- इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। गंगोपाध्याय (2009) बताते हैं कि भारत की बहुत अधिक आबादी अभी भी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से शामिल (डायरेक्ट फाइनेंशियली इनक्लूडेड) नहीं है। इस कदम से कई नए अकाउंट खुले हैं। बैंक ब्रांच बढ़ रही हैं, ATM, डेबिट कार्ड और कार्ट–स्वाइपिंग मशीनें बढ़ी हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। PayUIndia (ई–कॉमर्स पोर्टल), Paytm 'OlaMoney' ने अपने ई–वॉलेट में बढ़ोतरी दर्ज की है। जो कस्टमर पहले पेमेंट के लिए कैश मोड का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने ई–पेमेंट करना शुरू कर दिया है। भारत में एवरेज ट्रांजिट टाइम और कैश एक्सेस कॉस्ट के आधार पर कस्टमर के लिए कैश की कुल कॉस्ट अधिक है। नगद रहित अर्थव्यवस्था से अंतरण लागत (ट्रांजैक्शन कॉस्ट) कम होगी
- नगद रहित अर्थव्यवस्था सभी वित्तीय अंतरण का रिकॉर्ड रखेगी। वित्तीय अंतरण रिकॉर्ड करने से कई फायदे हैं। सरकार सही टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है और असरदार तरीके से काम कर सकती है।
- गैर–कानूनी लेन–देन, बिना हिसाब का पैसा (कालाधन) और गैर–कानूनी नोट तबाही मचाते हैं, जिससे पॉलिसी मेकर की कोशिशें बेअसर और बेकार हो जाती हैं। नोटबंदी से इस पर कुछ समय के लिए रोक लगेगी। बैंक इससे मुख्य फायदेमंद होंगे क्योंकि उनके पास नगद का अच्छा फ्लो हो रहा है।

- **नोटबंदी के नुकसान :–**

नोटबंदी के बाद के कुछ महीनों में लाखों गरीब और मिडिल क्लास लोग, जिनके पास खाना और दवा खरीदने के लिए नगद धन नहीं था, बैंकों और एटीएम से अपना पैसा

निकालने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहे थे। लोगों की नगद की आवश्यकता और नगद की उपलब्धता में बहुत अधिक अंतर था। नोटबंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हुये हैं–

- नोटबंदी के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में नगद धन का सर्कुलेशन बहुत धीमा हो गया था। नतीजतन, सभी सेक्टर में बिजनेस कम हो गया है क्योंकि कंज्यूमर जरूरत की चीजों पर खर्च को प्राथमिकता दे रहे थे।
- किसानों को सामान, खाद, बीज खरीदने और फसल बेचने में दिक्कत हो रही थीं। बड़े व्यापारी, खुदरा व्यापारी, छोटी और मीडियम इंडस्ट्री सभी को नुकसान हुआ था।
- हमारी अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है जो कि कैश पर निर्भर है।
- सप्लाई चेन में रुकावट आई और प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा था। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ठप हो गयी थी।
- रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी–पटरी वाले, घरेलू काम करने वाले और दिहाड़ी मजदूर – सिर्फ कमाने वाले ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास सभी पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा था। ट्रांसपोर्ट सर्विस, किराना, फल और सब्जियाँ और बाकी सभी सामान, डिमांड में कमी का सामना कर रहे हैं।
- नोटबंदी ने सप्लाई के साथ–साथ डिमांड पर भी असर डाला था, इससे बदले में कम कीमतों के बजाय महंगाई बढ़ी। देश मंदी की ओर बढा था और आर्थिक गतिविधियों में भी कमी आई थी।
- 500 और 1000 की करेंसी बैन ने नगद सप्लाई को बहुत कम कर दिया था, जिससे तत्काल में GDP में कुछ कमी आई थी, रोजगार के मौके कम हुए थे और अर्थव्यवस्था में कंजम्प्शन कम हुआ था।

यह अनुमान लगाया गया था कि इससे डिमांड में कमी के कारण टैक्स पर असर फायदेमंद होगा। सोने और लग्जरी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, हमने कैश बैलेंस को ऐसे मेटल

में बदलने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं कि GDP ग्रोथ, क्रेडिट एक्सपेंशन, इंटरेस्ट रेट और महंगाई के अंतर और एक्सचेंज रेट की उम्मीदों जैसे चार घरेलू फंडामेंटल के सस्टेनेबिलिटी पर भरोसा कम हुआ है। भरोसे में कमी ने न सिर्फ घरेलू इन्वेस्टर्स को बल्कि उनके विदेशी सहयागियों को भी प्रभावित किया है।

निष्कर्ष :–

हालांकि यह नोटबंदी नगद रहित अर्थव्यवस्था की ओर एक अच्छा कदम है, नगद धन बैंकों में जमा होने और सर्कुलेशन में वापस आने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था नाटकीय रूप से अपनी पुरानी स्थिति पर लौट गयी। लेकिन यदि अगर कालाधल सिस्टम में वापस नहीं आता तो पहले से ही सुस्त इन्वेस्टमेंट क्षेत्र के हालात में बढ़ोतरी एक चुनौती साबित हो सकता था। हॉलांकि भारत में एक अच्छा प्रतिस्पर्धात्मक टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, एक अच्छी तरह से विकसित आर्थिक वित्तीय व्यवस्था है, औरहम एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी निर्यातक हैं, फिर भी अभी भी बैंकिंग सिस्टम के साथ–साथ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े सुधार की जरूरत है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हेतु बैकबोन का काम करेगा। सस्ते फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक क्षेत्र, एक पारदर्शी व्यापार प्रक्रिया, ये सभी नगद रहित अर्थव्यवस्था की ओर तरक्की से बहुत जुड़े हुए हैं। कर व्यवस्था को आसान बनाना और कम करना, रेगुलेशन में कटौती करना, कमियों को खत्म करना और टैक्स बेस को बढ़ाना जरूरी है। रुपये की समस्या के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर के कुछ तरीके अभी भी काम के हैंः खुली अर्थव्यवस्था में डेप्रिसिएशन के फायदे, डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजों को ध्यान में रखने की जरूरत, घरेलू अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत, और मॉनेटरी मैनेजमेंट में समझदारी के बजाय नियमों को प्राथमिकता। कैशलेस अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव की उम्मीद और ज्यादा संभावना है।

संदर्भ सूचि :–

- **Jain, Meenu (2014)** "Globalization and Social Transformation: Indian Experience", *Research Process International Journal of the Social Research Foundation,Volume 2, Number 1, January–June 2014,Page No. 120-131*

- **Jain, Meenu (2015)** "Structural Change in the Course of Economic Development; India'sexperience", *Indian Journal of Applied Research, May 2015, Volume 5, Issue 5, Page No. 15-17*
- **Manivannan, P. (2013)** "Plastic Money away for Cash Less Payment System", *Global Research Analysis, Volume II, No. I, Page No. 19-28*
- **N Ramya, Sivasakthi; D. and Nandhini. M (2017)** "Cashless transaction: Modes, advantages and disadvantages", *International Journal of Applied Research 2017; Volume 3(1), Page No. 122-125*
- Rani, A. and Kumar, P. (2018) "Cashless economy: meaning, method & impact on economy", *Social Research Foundation Journal, Volume 9, Number 3, January–June 2017,Page No. 12-18*
- **Santomero, A. M. and Seater, J. J. (1996)** "Alternative monies and the demand for media of exchange", *Journal of Money, Credit and Banking, Volume 28(4), Page No. 942-960.*
- **Subhani, M. I. and Imtiaz,M. (2011)** "Plastic Money/Credit Cards Charisma for Now and Then: with emphasis on affordability and preference of them by consumers because of their convenience attribute during all kind ofdaily transactions", *European Journal of Scientific Research, Volume 6(1), Page No. 123-127.*
- **Parikh, Vinish (2017)** "Advantages and Disadvantages of Cashless Economy", April 23, http://www.letslearnfinance.com/advantages-disadvantages-cashless-economy.html